रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 मार्च, 2005/9 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 30 मार्च, 2005

संख्या वि0स0–विधायन–बिल/1–16/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग

4129–राजपत्र/2005–30–3–2005–1,424. (4355) मूल्य : 1 रुपया।

(संख्यांक 2) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 30 मार्च, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा ।

2005 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्तीय वर्ष 2005 – 2006 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2005 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2005 – 2006 के लिए 77,60,84, 95,000 रुपये की राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 77,60,84,95,000 (सतहत्तर अरब, साठ करोड़ चौरासी लाख पचानवे हजार रुपये) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाए, जिनका वित्तीय वर्ष 2005 – 2006 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा	(राजस्व)	7,14,61,000	20,07,000	7,34,68,000
		(पूंजी)	60,00,000	—	60,00,000
2	राज्यपाल और मंत्रि परिषद्	(राजस्व)	4,03,32,000	1,60,81,000	5,64,13,000
		(पूंजी)	—	—	—
3	न्याय प्रशासन और निवार्चन	(राजस्व)	33,23,29,000	6,70,80,000	39,94,09,000
		(पूंजी)	11,70,01,000	—	11,70,01,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	48,17,30,000	3,35,61,000	51,52,91,000
		(पूंजी)	5,00,000	—	5,00,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व)	1,98,18,37,000	—	1,98,18,37,000
		(पूंजी)	1,000	—	1,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	17,22,75,000	—	17,22,75,000
		(पूंजी)	—	—	—
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	2,19,60,90,000	—	2,19,60,90,000
		(पूंजी)	10,90,04,000	—	10,90,04,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	9,64,25,30,000	—	9,64,25,30,000
		(पूंजी)	23,12,01,000	—	23,12,01,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व)	2,86,15,66,000	—	2,86,15,66,000
		(पूंजी)	40,56,80,000	—	40,56,80,000
10	लोक निर्माण—भवन	(राजस्व)	1,27,07,58,000	—	1,27,07,58,000
		(पूंजी)	17,94,26,000	—	17,94,26,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
11	कृषि	(राजस्व)	69,13,70,000	—	69,13,70,000
		(पूंजी)	19,65,00,000	—	19,65,00,000
12	उद्यान	(राजस्व)	49,53,22,000	—	49,53,22,000
		(पूंजी)	2,36,34,000	—	2,36,34,000
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	68,40,28,000	—	68,40,28,000
		(पूंजी)	1,43,12,74,000	—	1,43,12,74,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	64,06,91,000	—	64,06,91,000
		(पूंजी)	3,58,75,000	—	3,58,75,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व)	72,55,59,000	—	72,55,59,000
		(पूंजी)	21,02,01,000	—	21,02,01,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	1,44,90,50,000	—	1,44,90,50,000
		(पूंजी)	1,73,01,000	—	1,73,01,000
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	3,38,39,25,000	—	3,38,39,25,000
		(पूंजी)	1,55,45,01,000	3,00,00,000	1,58,45,01,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	20,71,25,000	—	20,71,25,000
		(पूंजी)	5,32,00,000	—	5,32,00,000
19	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	(राजस्व)	1,27,04,03,000	—	1,27,04,03,000
		(पूंजी)	13,89,68,000	—	13,89,68,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	1,01,94,74,000	—	1,01,94,74,000
		(पूंजी)	3,55,44,000	—	3,55,44,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	10,51,22,000	—	10,51,22,000
		(पूंजी)	1,29,63,000	—	1,29,63,000
22	खाद्य और भाण्डागारण	(राजस्व)	11,08,43,000	—	11,08,43,000
		(पूंजी)	50,04,000	—	50,04,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	91,44,54,000	—	91,44,54,000
		(पूंजी)	24,00,01,000	—	24,00,01,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	9,18,14,000	—	9,18,14,000
		(पूंजी)	20,00,000	—	20,00,000
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	30,65,02,000	—	30,65,02,000
		(पूंजी)	11,30,00,000	—	11,30,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	3,67,75,000	—	3,67,75,000
		(पूंजी)	65,00,000	—	65,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	22,29,02,000	—	22,29,02,000
		(पूंजी)	7,33,50,000	—	7,33,50,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	3,37,28,44,000	—	3,37,28,44,000
		(पूंजी)	1,20,14,50,000	—	1,20,14,50,000
29	वित्त	(राजस्व)	6,70,49,66,000	17,23,05,76,000	23,93,55,42,000
		(पूंजी)	10,96,01,000	9,28,70,79,000	9,39,66,80,000
30	विविध सामान्य सेवायें	(राजस्व)	20,59,06,000	—	20,59,06,000
		(पूंजी)	1,77,01,000	—	1,77,01,000
31	जन जातीय विकास	(राजस्व)	2,09,90,28,000	—	2,09,90,28,000
		(पूंजी)	62,57,19,000	—	62,57,19,000
		(राजस्व)	**43,78,90,11,000**	**17,34,93,05,000**	**61,13,83,16,000**
		(पूंजी)	**7,15,31,00,000**	**9,31,70,79,000**	**16,47,01,79,000**
		(जोड़)	**50,94,21,11,000**	**26,66,63,84,000**	**77,60,84,95,000**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2005 - 2006 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख 30 मार्च, 2005.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग नस्ति संख्या फिन ए.सी. (1) 7/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2005 की विषय - वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2005-2006.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2005.

Issue of a sum of Rs. 77,60, 84,95,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2005-2006.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to a sum of Rs. 77,60,84,95,000 (Seventy seven hundred sixty crores, eightyfour lakhs, ninety five thousand rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2005-2006 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha	(Revenue)	7,14,61,000	20,07,000	7,34,68,000
		(Capital)	60,00,000	—	60,00,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	4,03,32,000	1,60,81,000	5,64,13,000
		(Capital)	—	—	—
3	Administration of Justice and Election	(Revenue)	33,23,29,000	6,70,80,000	39,94,09,000
		(Capital)	11,70,01,000	—	11,70,01,000
4	General Administration	(Revenue)	48,17,30,000	3,35,61,000	51,52,91,000
		(Capital)	5,00,000	—	5,00,000
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	1,98,18,37,000	—	1,98,18,37,000
		(Capital)	1,000	—	1,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	17,22,75,000	—	17,22,75,000
		(Capital)	—	—	—
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	2,19,60,90,000	—	2,19,60,90,000
		(Capital)	10,90,04,000	—	10,90,04,000
8	Education	(Revenue)	9,64,25,30,000	—	9,64,25,30,000
		(Capital)	23,12,01,000	—	23,12,01,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	2,86,15,66,000	—	2,86,15,66,000
		(Capital)	40,56,80,000	—	40,56,80,000
10	Public Works—Building	(Revenue)	1,27,07,58,000	—	1,27,07,58,000
		(Capital)	17,94,26,000	—	17,94,26,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
11	Agriculture	(Revenue)	69,13,70,000	—	69,13,70,000
		(Capital)	19,65,00,000	—	19,65,00,000
12	Horticulture	(Revenue)	49,53,22,000	—	49,53,22,000
		(Capital)	2,36,34,000	—	2,36,34,000
13	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	68,40,28,000	—	68,40,28,000
		(Capital)	1,43,12,74,000	—	1,43,12,74,000
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue)	64,06,91,000	—	64,06,91,000
		(Capital)	3,58,75,000	—	3,58,75,000
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue)	72,55,59,000	—	72,55,59,000
		(Capital)	21,02,01,000	—	21,02,01,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	1,44,90,50,000	—	1,44,90,50,000
		(Capital)	1,73,01,000	—	1,73,01,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	3,38,39,25,000	—	3,38,39,25,000
		(Capital)	1,55,45,01,000	3,00,00,000	1,58,45,01,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	20,71,25,000	—	20,71,25,000
		(Capital)	5,32,00,000	—	5,32,00,000
19	Social Justice and Empowerment	(Revenue)	1,27,04,03,000	—	1,27,04,03,000
		(Capital)	13,89,68,000	—	13,89,68,000
20	Rural Development	(Revenue)	1,01,94,74,000	—	1,01,94,74,000
		(Capital)	3,55,44,000	—	3,55,44,000
21	Co-operation	(Revenue)	10,51,22,000	—	10,51,22,000
		(Capital)	1,29,63,000	—	1,29,63,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	11,08,43,000	—	11,08,43,000
		(Capital)	50,04,000	—	50,04,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
23	Water and Power Development	(Revenue)	91,44,54,000	—	91,44,54,000
		(Capital)	24,00,01,000	—	24,00,01,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	9,18,14,000	—	9,18,14,000
		(Capital)	20,00,000	—	20,00,000
25	Road and Water Transport	(Revenue)	30,65,02,000	—	30,65,02,000
		(Capital)	11,30,00,000	—	11,30,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	3,67,75,000	—	3,67,75,000
		(Capital)	65,00,000	—	65,00,000
27	Labour Employment and Training	(Revenue)	22,29,02,000	—	22,29,02,000
		(Capital)	7,33,50,000	—	7,33,50,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	3,37,28,44,000	—	3,37,28,44,000
		(Capital)	1,20,14,50,000	—	1,20,14,50,000
29	Finance	(Revenue)	6,70,49,66,000	17,23,05,76,000	23,93,55,42,000
		(Capital)	10,96,01,000	9,28,70,79,000	9,39,66,80,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	20,59,06,000	—	20,59,06,000
		(Capital)	1,77,01,000	—	1,77,01,000
31	Tribal Development	(Revenue)	2,09,90,28,000	—	2,09,90,28,000
		(Capital)	62,57,19,000	—	62,57,19,000
		(Revenue)	**43,78,90,11,000**	**17,34,93,05,000**	**61,13,83,16,000**
		(Capital)	**7,15,31,00,000**	**9,31,70,79,000**	**16,47,01,79,000**
		Grand Total	**50,94,21,11,000**	**26,66,63,84,000**	**77,60,84,95,000**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the year 2005-2006.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
the 30th March, 2005.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C (1) 7/2004]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित